पेट्रोल डीजल की कीमतों में मची भयंकर लूट को ध्यान से समझ लीजिए

अंतराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम एक बार फिर पानी से भी कम हो गए हैं लेकिन कीमतें गिरने का फायदा भारत में ग्राहकों को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खबर आ रही है कि मोदी सरकार 6 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी और बढ़ा सकती है। जबकि कोरोना काल मे पहले ही मई 2020 में पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर ड्यूटी बढ़ाई जा चुकी है।

आपके होश उड़ जाएंगे यदि आप यूपीए के कार्यकाल की एक्साइज ड्यूटी की तुलना आज की एक्साइज ड्यूटी से करेंगे ! 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के आने से पहले मनमोहन सरकार में 1 अप्रैल 2014 को सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर प्रति लीटर मात्र 9.48 रूपए और डीजल पर मात्र 3.56 रूपए थी. जबकि आज पेट्रोल पर टैक्स बढ़कर 32.98 प्रति लीटर और डीजल पर टैक्स 31.83 रुपए प्रति लीटर है. यानी मात्र छह सालों में पेट्रोल पर एक्साइज में 23.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 28.27 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है

सिर्फ 6 सालो में पेट्रोल पर साढ़े तीन गुना से अधिक ओर डीजल पर लगभग 10 गुना बढोत्तरी हुई है अब बताइये देश की जनता को कौन लूट रहा है बेशक कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने अपने राज्यों में पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाया है लेकिन उनके पास अपने खर्च चलाने का और कोई रास्ता नही है क्योंकि 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद वह अन्य मद में टैक्स लगाने के अधिकार को खो चुके हैं।

पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को मोदी सरकार दुधारू गाय समझ कर एक बार फिर दुहने जा रही है । 2014 से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बारह बार बढ़ चुकी है और घटी है सिर्फ दो बार. जबकि कच्चे तेल की कीमतें लगातार घटती ही गयी 2014 में नरेंद्र मोदी की ताजपोशी से एक साल से भी कम समय में कच्चे तेल की कीमत 114 डॉलर प्रति बैरल पर पुहंच गयी थी जबकि आज कच्चे तेल के दाम 37 डॉलर प्रति बैरल है।

एक बार आप खुद सोचिए कि 2014 में तब इतनी अधिक एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती तो पेट्रोल के दाम लगभग 200 रु प्रति लीटर पर पुहंच जाते लेकिन यूपीए ने उस पर कंट्रोल किया लेकिन मोदी सरकार ने इसे ही लूट का जरिया बना लिया। कल एक बार फिर यूरोप में लॉक डाउन की संभावना से कच्चे तेल के दाम गिरे है, मौजूदा समय में कच्चे तेल के दाम 37 डॉलर प्रति बैरल है। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। एक डॉलर की कीमत 74 रुपये है। इस लिहाज से एक बैरल की कीमत 2733 रुपये बैठती है. वहीं, अब एक लीटर में बदलें तो इसकी कीमत 17.18 रुपये के करीब आती है, जबकि देश में बोतलबंद पानी की कीमत 20 रुपये के करीब है। इसका फायदा जनता को देने के बजाए 6 रु एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है।

कुछ भक्त किस्म के लोग कहेंगे कि मोदी जी ने इस रकम से देश के विदेशी कर्जे चुकाए है लेकिन उन्हें यह बात जान लेना चाहिए कि जून, 2014 में सरकार पर कुल कर्ज 54,90,763 करोड़ रुपये था, जो आज 2020 में बढ़कर 100 लाख करोड़ रुपये के पार हो गया है यानी लगभग इन 6 सालो में पिछले 65 सालों में इकठ्ठे कर्ज से दोगुना कर्ज ले लिया गया है।

अब कोई यह एक्सप्लेन करे कि कच्चे तेल का आयात बिल जो देश के सबसे बड़े खर्चो में शुमार किया जाता हैं उसके अंतर्गत तो नसीब वाली मोदी सरकार को बेतहाशा फायदा पुहंचा है तो फिर कर्ज दोगुना कैसे हो गया ?

श्रम

थ्योरी कुछ प्रेक्टिकल कुछ : एस्कॉर्टस यूनियन का 'आज'

सतीश कुमार

फ़रीदाबाद में एचएमएस को जन्म देनवाली ऑल एस्कॉर्टस इम्पलायज़ यूनियन की आज क्या स्थिति है और वह यहां तक कैसे पहुंची, इसे जानना मज़दूर वर्ग के लिये बहुत जरूरी है। एचएमएस के साथ नाभि-नाल का सम्बन्ध रखने वाली एस्कॉर्टस यूनियन खुद तो रसातल में गयी सो गयी साथ में एचएमएस को भी ले डूबी। किसी जमाने में 12500 सदस्यों वाली इस यूनियन में आज मात्र 1750 सदस्य ही रह गये हैं। कभी सूरजपुर (नोयडा) वाले याहमा प्लांट सहित आठ प्लांटों तक फैला इसका साम्राज्य सिकुड़ कर आज केवल चार प्लांटों तक ही रह गया है। इन प्लांटों में भी आधे से अधिक मज़दूरों को अछूतों की तरह यूनियन से दूर रखा गया है क्योंकि वे नियमित अथवा पक्के नहीं हैं। कम्पनी का 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक काम यही कच्चे मज़दूर निपटा देते हैं। जाहिर है, इन हालात में कम्पनी की निर्भरता इन कच्चे मज़दूरों पर ही अधिक है जो हर प्रकार का शोषण, उत्पीड़न व अपमान सहने को मजबूर हैं।

ऑटो मोबाइल की इस कम्पनी की यूनियन को विशाल एवं सुदृढ रूप देने में यूं तो अनेकों मज़दूरों ने अपना तन, मन, धन इसमें खपा दिया परंतु सबसे अधिक उभर कर, सर्वमान्य नेता के रूप में सुभाष सेठी आये थे जो मोटर साइकिल प्लांट में कार्यरत थे। उनकी संगठनात्मक क्षमता को भांपते हुए कंपनी ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया था।

असल में सेठी के नेतृत्व में बाइक प्लांट 1973 में हड़ताल पर चला गया था। बदले की कार्यवाही करते हुए कम्पनी ने सेठी से व 26 अन्य मज़दूरों को बर्खास्त कर दिया था। दिल्ली इन्जीनियरिंग कॉलेज से आटो मोबाइल का डिप्लोमा धारक सेठी ने कहीं और नौकरी ढूंढने की अपेक्षा एस्कॉर्टस कम्पनी के सभी प्लांटों की एक बड़ी यूनियन ऑल एस्कार्टस इम्पलाइज़ के नाम से बनाने का बीड़ा उठाया।

यूनियन बनी उसे रजिस्ट्रेशन नम्बर भी वही मिला जो सेठी की बाइकप्लांट यूनियन का था। इस बड़ी यूनियन बनाने के पीछे सेठी की रणनीति यह थी कि किसी भी एक प्लांट के मज़दूरों द्वारा किये जाने वाले संघर्ष एवं हड़ताल आदि से इतनी बड़ी कम्पनी पर कोई खास दबाव नहीं बनता; इस लिये पूरा दबाव बनाने के लिये सभी प्लांटों को एक जुट होना होगा। ऑल एस्कॉर्टस इम्पलाइज़ यूनियन गठित होने के बाद दिये जाने वाले हर मांग पत्र में पहली मांग सेठी की बहाली रखी जाती थी। लेकिन कामयाबी मिली 1983 में, यानी पूरे 10 साल बाद। इस बीच जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी। इतनी बड़ी यूनियन का प्रधान होने के नाते सेठी ने अपनी पहुंच जॉर्ज फ़र्नांडीस, मधु दंडवते, सुरेन्द्र मोहन, सुषमा स्वराज, राम विलास पासवान, चन्द्रशेखर,वीपी सिंह तथा देवी लाल सरीखे बड़े नेताओं तक बना ली थी।

बड़ी यूनियन के प्रधान होने का जो दबाव कम्पनी पर होता है उसके साथ-साथ सेठी की राजनीतिक पहुंच का भी दबाव कम्पनी पर अच्छा-खासा पड़ रहा था। इसके साथ-साथ सेठी का यह कहना कि वे कम्पनी के विरुद्ध नहीं हैं, कम्पनी के अस्तित्व के बिना उनका (मज़दूरों का) भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। वे तो केवल इतना चाहते हैं कि जो मज़दूर कम्पनी को कमा कर दे रहे हैं, उनका हक भी उन्हें मिलना चाहिये। उक्त तीनों बातों से प्रभावित कम्पनी जो विभिन्न ट्रेड यूनियनों (एटक, इंटक, सीटू) के बाहरी नेताओं से परेशान रहती थी, ने सेठी को नौकरी पर बहाल करना बेहतर समझा, कम से कम वे कम्पनी के मज़दूर तो हैं। लेकिन इनके साथ बर्खास्त हुए अन्य 26 मज़दूरों का कोई अता-पता नहीं चल पाया, वे कौन से गर्त में समा गये।

कई बड़े मजदूर नेता वक्त की आंधी में उड़कर भाजपाई हो गये

शुरू में हर तरह की चुनौतियां आई। विभिन्न ट्रेड यूनियनों से जुड़े मज़दूरों ने नेतृत्व हथियाने के पुरजोर प्रयास किये परन्तु सेठी ने अपनी संगठनात्मक सूझ-बूझ के चलते उन सबको परास्त कर अपना एकछत्र नेतृत्व स्थापित किया।

शुरूआती काल में जो मज़दूर बतौर चंदा एक रुपया देने में भी हील-हुज्जत करते थे वही मज़दूर 100-100 रुपये सालाना भी देने लगे, बोनस एवं एग्रीमेंट आदि पर भी यूनियन द्वारा मांगे जाने वाले चंदे को सहर्ष देने लगे। जिस कम्पनी प्रबन्धन ने सेठी को निकाल बाहर किया था और यूनियन को पहचानती नहीं थी वही प्रबन्धन यूनियन के सामने नतमस्तक होने लगा था। और तो और यूनियन द्वारा घोषित चंदे की उगाही भी मज़दूरों के वेतन से काट के यूनियन के बैंक खाते में डालने लगा। यूनियन की शायद ही कोई ऐसी मांग हो जिसे प्रबन्धन ने स्वीकार न किया हो। अपनी नौकरी वापस पाने के लिये सेठी ने अदालतों के धक्के खाने की बजाय अपने संगठन पर अधिक बल्कि पूरा भरोसा किया और पिछले पूरे वेतन सहित नौकरी पर बहाली पायी।

यूनियन का यह स्वर्णिम दौर था। मज़दूरों के निरंतर आ रहे चंदे से नीलम फ्लाई ओवर की बगल में शानदार दो मंजिला दफ़्तर बन गया, 2-3 करोड़ की एफ़डी (सावधि जमा राशि) विभिन्न बैंकों में जमा हो गयी। इसी रकम के ब्याज मात्र से दफ्तर का खर्च चलने लगा। यूनियन दफ्तर के पीछे खुले पड़े मैदान को जब एस्कॉर्टस कम्पनी ने सरकार से झटक लिया तो उसमें से 500-700 गज़ जगह यूनियन ने भी कम्पनी से झटक ली। यह यूनियन की ताकत का ही परिणाम था जो आज तक भी इस दफ़्तर का बिजली, पानी व सीवर एस्कॉर्टस अस्पताल के जिम्मे है।

एचएमएस बेशक सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल से सम्बन्धित नहीं रही, लेकिन इसका जुड़ाव अपने आपको समाजवादी कहने वाले उन नेताओं से रहा जो वक्त की आंधी में उड़ कर बाद में भाजपाई तक हो गये। इसी सिद्धांत के आधार पर एचएमएस से जुड़ी हर यूनियन को किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखने की छूट रही है। सुभाष सेठी एक ओर तो व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की बात करते थे, भगत सिंह की राह अपनाने की कहते थे, दूसरी ओर वे उक्त तमाम सिद्धांतहीन नेताओं की परिक्रमा करते थे। इनमें से कोई भी नेता जब दिल्ली से चल कर मथुरा की ओर जाता था तो एस्कॉर्ट गेट पर मज़दूरों की भारी भीड़ जुटा कर उनका स्वागत, सत्कार एवं जय-जयकार किया जाता था। यह सब करते वक्त सेठी भूल जाते थे कि एक जनता पार्टी में होते हुए भी इनमें भारी अन्तरविरोध हैं। सेठी को इस बात का अनुभव शायद पहली बार तब हुआ जब औम प्रकाश चौटाला ने सेठी को जार्ज फ़र्नांडीस से मिल कर निकलते देखा और उन्हें यह कहते हुए धमकाया कि दिखावा तो हमारे साथ रहने का करते हो और छिप-छिप कर उनसे भी मिलते हो। इसी के चलते 1982 में विधानसभा की बल्लबगढ सीट से चौटाला ने उनका टिकट कटवा दिया। तमाम मिन्नत समाजत के बावजूद जब देवी लाल नहीं माने तो जॉर्ज से दबाव डलवा कर बड़ी मुश्किल से देवी लाल से टिकट लिया। परन्तु इतनी जद्दो-जहद के बावजूद सेठी चुनाव हार गये।

दरअसल हर इंसान, जो थोड़ा-बहुत भी किसी संगठन से जुड़ जाता है। उसकी इच्छा राजनीतिक सत्ता पाने की होती है, यह स्वाभाविक भी है। फ़िर सेठी तो बहुत बड़ी यूनियन के प्रधान थे। उनके राजनीतिक संपर्क भी काफ़ी हो गये थे, अनेकों राज्य व राष्ट्रीय स्तर के नेता उनसे जुड़े थे। ऐसे में विधायक बनने की इच्छा का होना कोई अनहोनी बात नहीं। ऐसे में हर मज़दूर नेता की तरह सेठी ने भी यही सोचा होगा कि विधायक बनने के बाद वे मज़दूरों के हित में ज्यादा बढिया लड़ाई लड़ सकेंगे।

(सम्पादक : मजदूर मोर्चा)